16.30 hrs.

RESOLUTION RE: TIBET

Mr. Speaker: The House will now take up the next Resolution standing in the name of Shri Shri Chand Goel, for which two hours have been allotted.

Shri P. K. Deo: *(Kalahandi): Sir,* may I suggest the time for this Resolution may be reduced from 2 hours to 1½ hours so that Shri Tapuriah may be able to move his Resolution today?

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) If that is the unanimous demand of the House, then I will bow to it.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): When generally the demand is to increase the time, here is a demand for reducing the time allotted to a Resolution.

Shri M. L. Sondhi (New Delhi): Sir, may I suggest that the time for this Resolution should be increased?

Shri Ranga (Srikakulam): If we sit for one hour extra, we can take up the other Resolution today itself.

Mr. Speaker: We will see. Now, Shri Goel.

श्री श्रीचन्द गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस अपने प्रस्ताव को सदन के सामने रखता हूं जिस में यह मांग की गई है कि आज समय आ गया है कि भारत सरकार भारत मे शरणागत के रूप में आये हुए लामा को तिब्बत का कांस्टीटयूशनल हैड, वैधानिक शासक स्वीकार कर के सब को सब प्रकार की सहायता और सुविधा प्रदान करे और तिब्बत जैसे महान देश को कम्युनिस्ट चीन के चंगुल से निजात दिलाने का प्रयत्न करे । अध्यक्ष महोदय, तिब्बत संसार का महान देश था और भारत के साथ इस की हर प्रकार की निकटता रही है । चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में, चाहे धार्मिक क्षेत्र में चाहे आर्थिक क्षेत्र में हर क्षेत्र में भारत के साथ इस की एकात्मता रही है । वास्तव में जब हम तिब्बत के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो दिखाई देता है कि आज से ढाई हजार वर्ष पहले महात्मा बुद्ध के समकालीन कौशल वंश के राजा प्रसेनजित के पुत्र ने भारत से जाकर तिब्बत में राज्य स्थापित किया था और धीरे धीरे तिब्बत राष्ट्र उन्नतोन्मुख होना चला गया, *सब प्रकार से अपनी उन्नति करता चला गया ।* लेकिन किसी भी राष्ट्र के जीवन मे उतार चढाव आते है । इतिहास ऐसा बताता है कि एक बार जब तातारियों ने तिब्बत पर आक्रमण किया तो उस समय चीन मे माचू राजवंश के राजा जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उन का वहां पर राज्य था । उस समय तिब्बत ने चीनियों से सहायता मांगी और वह सहायता मिली । उस सहायता के मिलने के बाद जब तातारियो का मुकाबिला कर पाये उसके परिणामस्वरूप फिर चीन का एक एजेंट ल्हासा मे रहने लगा । लेकिन यह इतिहास की पुरानी घटना है । उस के बाद अनेकों वर्ष का तिब्बत का जो इतिहास है वह स्वतंत्रता का इतिहास है । तिब्बत हमेशा दूसरे देशों के साथ में स्वतंत्र रूप मे सन्धि करता रहा, स्वतंत्र रूप मे अपना सारा कारोबार करता रहा । अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1904 मे ब्रिटेन ने तिब्बत के साथ ल्हासा सन्धि की थी चूंकि उन को तिब्बत में कुछ खतरा दिखाई देता था । परन्तु वह तिब्बत को भारत के लिए एक "बफर" स्टेट के रूप मे समझते थे । अंग्रेजों ने अपनी सारी नीति भारत की सुरक्षा के लिये इस ढंग से बनाई थी, दूर दूर तक जाकर भारत के चारों तरफ ऐसी "बफर" स्टेट कायम की थी, इसलिये उत्तरी सीमा पर उन्हे दिखाई दिया कि कुछ गडबड़ है तो अपना मिशन भेजा और उसके बाद 1904 मे एक सन्धि की । उस के बाद 1911 में जब चीन के अन्दर क्रान्ति आयी और माचू राजवंश की हुकूमत चीन मे समाप्त हो गई तो उस समय तिब्बत वालों ने भी जो चीनी सन्धियां थी या जो चीनी आधिपत्य था उस को समाप्त कर दिया था ।

[श्री श्रीचन्द गोयल]

इस के बाद मैं एक श्रौर ऐतिहासिक घटना की श्रोर ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1913-14 में शिमला कन्वेंशन, श्रर्थात् शिमला सम्मेलन हुश्रा जिस के श्रन्दर चीन का प्रतिनिधि, तिब्बत का प्रतिनिधि श्रौर भारत का प्रतिनिधि शिमला में एक मंच के ऊपर श्राकर बैठे। तीनों ने बिलकुल बराबरी के स्तर से, बराबरी के स्टेटस के साथ संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए। लेकिन बाद में जब चीन ने इस प्रकार की पोजीशन ली कि श्रपने प्रतिनिधि के हस्ताक्षरों की मान्यता देने से इन्कार किया तो इस सधि के श्रनुसार श्रगर उन का कुछ थोड़ा बहुत श्राधिपत्य बाकी था तो उस का हक भी उन्होंने स्वयं नष्ट कर दिया, स्वयं खो दिया।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इतिहास की उस घटना पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि जिस समय चीन में कम्यूनिस्टों की हुकूमत कायम हुई तो हमारे लिए चिन्ता की घड़ी पैदा हुई उस समय भारत के कर्णधारों को इस बात का विचार करना चाहिए था कि श्रब चीन की स्थिति बदल गई है। चीन के साथ जो हमारे मैत्री के संबंध थे उस के दो कारण थे। एक कारण तो था भौगोलिक दूरी। चूंकि तिब्बत बफर स्टेट के रूप में हमारे श्रौर इन के बीच में था श्रौर दूसरे उन की यह भी विचार करना चाहिए था कि चीन के साथ हमारी जो सांस्कृतिक एकता थी वह महात्मा बुद्ध के श्रादर्शों के प्रचार के कारण पैदा हुई सांस्कृतिक निकटता थी लेकिन जिस समय कम्यूनिस्टों की हुकूमत कायम हो गई तो हमें यह पहचान लेना चाहिए था, कोई भी राजनीतिज्ञ जो थोड़ी बहुत भी दूरदर्शिता रखता है जो दस बीस पचास साल श्रागे की बात सोच सकता है उस की समझ में यह बात श्रा जानी चाहिए थी, कि जो चीन की श्रौर हमारी पिछली मैत्री थी उस का श्राधार समाप्त हो चुका है। कहावत है, एक तो करैला श्रौर दूसरे नीम चढ़ा। पहले से ही चीन एक विस्तारवादी मनोवृत्ति का देश था। श्राज मुझें हैरानी होती है, जब मैं नेहरू जी की उस समय की स्पीचेज़ को याद करता हूं, उस समय जब यह कहा जाता था कि चीन हमें धोखा देता, चीन एक विस्तारवादी देश है, एक एक्सपैंशनिस्ट कन्ट्री है, जो नेहरू जी कहते थे कि चीन तो विस्तारवादी मनोवृत्ति का देश है ही नहीं। मगर मैं बताना चाहता हूं कि चीन का जो इतिहास है उस को गौर से पढ़ा जाय तो हमें पता चलता है कि शुरू से ही चीन एक विस्तारवादी देश रहा है, चीन का क्षेत्रफल जब चीन श्रपनी प्रसिद्ध चीन की दीवार तथा समुद्र से घिरा था तो केवल 10 लाख वर्ग मील था। लेकिन पिछले ढाई हजार वर्षों में इस ने श्रपना क्षेत्रफल 26 लाख वर्गमील बना लिया है, ढाई गुना के करीब श्रपना क्षेत्र बढ़ाया है लेकिन जिस समय श्राठ लाख वर्गमील के क्षेत्रफल का तिब्बत उस में शामिल हो गया तो इस का क्षेत्रफल 30 लाख वर्गमील से भी ज्यादा हो गया। उन की श्राज श्राबादी भारत से डेढ़गुनी है। लेकिन चीन का रकबा भारत से तीन गुना है। श्राज जब यह दलील दी जाती है कि चीन को श्रपनी बढ़ती हुई श्राबादी के लिये कोई इलाका चाहिये, तो यह एक बिल्कुल थोथी श्रौर बोदी दलील है। उनका क्षेत्रफल श्राबादी की तुलना में पहले ही बहुत है—उनका विस्तारवाद तो राजनैतिक है क्योंकि उन का क्षेत्रफल हमारे से तीन गुना है, परन्तु चीन एक विस्तार वादी देश है, शुरू से उसकी इधर उधर पांव फैलाने की मनोवृत्ति रही है। साम्यवाद भी विस्तावादी है। साम्यवाद का संसार में यह लक्ष्य रहा है कि संसार को श्रपनी लपेट में लें, श्रपनी विचारधारा संसार के देशों में फैलाये इसी लिये चीन में कम्यूनिस्टों की हुकूमत कायम होने के बाद हमें यह विचार करना चाहिये था कि साम्यवाद का उत्तर ध्रुव तक विस्तार हो गया है, तथा

इसी प्रकार से एटलांटिक सागर से शान्त महासागर तक वहां और आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, गुन्जाइश केवल दक्षिण में है। ऐसी स्थिति में दक्षिण की तरफ भारत उसकी लपेट में आयेगा, नेपाल उसकी लपेट में आयेगा, सिक्किम और भूटान उसकी लपेट में आयेंगे, दूसरे जो इसी प्रकार के वैस्ट एशिया के देश हैं, वे उसकी लपेट में आयेंगे। लेकिन उस समय हम ने हकीकत से आंखें मूंद लीं। सरदार पटेल कहा करते थे कि अगर कोई भी राष्ट्र हकीकत से, सच्चाई से आंखें मूंदता है तो समय उस से बदला लेगा, और उस ने वह बदला लिया। हम ने उस समय सच्चाई को नहीं पहचाना कि चीन के साथ अब हमारी मैत्री नहीं निभ सकती।

जिस समय वहां पर साम्यवाद का साम्राज्य कायम हुआ, उसी वक्त से उन्होंने इस बात की उधेड़बुन शुरू कर दी कि वह किसी न किसी तरीके से तिब्बत पर अपना अधिकार जमाये, तिब्बत को हस्तगत करे, उसको अपने कब्जे में ले। मैं उस इतिहास की याद दिलाना चाहता हूं जिस समय एक श्रेष्ठ मिशनरी पैटर्सन भारत आया, बड़े दुर्गम रास्तों से भारत आकर वह नेहरू जी से मिला और उसने नेहरू जी को बतलाया कि तिब्बत पर चीन की कुदृष्टि है वह उसको अपने कब्जे में लेने का प्रयत्न कर रहा है। इसलिये तिब्बत की कुछ न कुछ सहायता करें। परन्तु तिब्बत की सहायता नहीं की गई। आज मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि उस समय उस ईसाई मिशनरी पैटर्सन ने बड़े पते की बात हमारे देश के हित में बताई थी और वह इस आशा से आया था कि भारत तिब्बत की सहायता करेगा और चीन के चंगुल से उसे बचा लेगा परन्तु उसकी बात की तरफ़ ध्यान नहीं दिया गया। उसकी बात को ठुकरा दिया गया। पैटर्सन ने अपनी एक किताब निकाली है उसमें उस ने इन सारी बातों का वर्णन किया है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय यह स्थिति पैदा हुई, उस समय जो हमारे राजदूत श्री पाणिकर थे, उनका यह कर्तव्य था कि वह सारी सच्चाई, सारे हालात को भारत सरकार की दृष्टि में लाते, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। उन्होंने भारत को अन्धेरे में रखा। हमारी इस सरकार ने न सिर्फ भारत की जनता को अन्धेरे में रखा, बल्कि इस संसद् को भी उन्होंने धोखे में रखा। जिस समय वहां पर लम्बी लम्बी सड़कें बन रही थीं, दूसरी तैयारियां हो रही थीं, उनकी सेनायें हमारे क्षेत्र के अन्दर कभी लौंगजू पर कभी दूसरी जगहों पर आक्रमण करती थीं, और जब यहां लोक सभा में सवाल पूछे जाते थे तो यह कहा जाता था कि हमें उधर से कोई खतरा नहीं है। सरकार को तिब्बत के सम्बन्ध में पता कब चला ? सरकार को पता चला--24 अक्तूबर, 1950 को जिस समय पाकिंग रेडियो ने ऐलान किया कि चीन की जो लिब्रेशन सेनायें, मुक्ति सेनायें हैं, वे तिब्बत में बढ़ रही हैं। नेहरू जी के नोटिस में जब यह बात आई तो उन्होंने कहा कि लिब्रेशन सेनायें किससे मुक्ति दिला रही हैं, परन्तु प्रश्न का उत्तर मिलने से पहले ही तिब्बत चीन के कब्जे में आ चुका था। वह वहां पर कब्जा कर चुका था। उस समय हमारा यह कर्तव्य था कि हम तिब्बत का साथ देते। तिब्बत का बफर स्टेट के रूप में भारत की सुरक्षा की दृष्टि से कायम रहना निहायत ज़रूरी था।

दूसरी बात जब 1947 में भारत से अंग्रेज चले गये, जो अंग्रेज सरकार के अधिकार उस समय तिब्बत में थे, उदाहरणार्थ हमारा अपना डाक-तार का सिलसिला वहां पर था, हमारे व्यापारी इन तिब्बत के बड़े बड़े नगरों में रहते थे, तिब्बत का सारा व्यापार भारत के साथ था, वे सारे अधिकार हमें प्राप्त हुए थे, तो हमारा यह कर्तव्य था कि हम

[श्री श्रीचन्द गोयल]

तिब्बत की हर प्रकार से मदद करते । लेकिन हमने क्या किया ? हमने तिब्बत की मदद नहीं की, हमने उस समय तिब्बत को इन चीनी भेड़ियों का भक्ष्य होते देखा, हर प्रकार से उसका बलात्कार होते देखा । आज भारत इस बात का दावा करता है कि संसार के सब राष्ट्रों को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये, अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार एक राष्ट्र दूसरे देश पर अधिकार नहीं कर सकता, लेकिन हम ने क्या किया ? अपनी आंखों के सामने यह सारा दृश्य देखा और तिब्बत को चीन का भक्ष्य बनने दिया, हम ने उस की किसी प्रकार की सहायता नहीं की । जब उन्होंने सहायता मांगी, तो भी हमने सहायता नहीं दी ।

जब महात्मा बुद्ध की 2500वीं जयन्ती मनाई जा रही थी, उस समय लामा यहां आये थे, वह नेहरू जी से मिले थे, उन्होंने उनसे प्रार्थना की थी कि आप हमारी सहायता करें, तब भी नेहरू जी ने उनको यह समझा बुझा कर भेज दिया कि हम चीन की साम्यवादी सरकार को लिखेंगे कि वह तिब्बत के इन्टरनल मामलों में दखल न दे । लेकिन आखिर में आपको याद होगा कि 1959 में जब तिब्बत की बहादुर जनता ने वहां एक जन आन्दोलन खड़ा किया, वहां के खम्पाओं ने तिब्बत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिये आन्दोलन खड़ा किया, क्योंकि स्थिति यह थी कि जब वहां पर रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तो 5 लाख तिब्बतियों को चीन ने संगीन की नोक पर रेल लाइन के निर्माण कार्य में लगाया था, हजारों लोगों को उस समय तलवार के घाट उतार दिया गया था । 60-70 हजार नौजवानों ने अपना बलिदान दिया था, इस कारण खम्पाओं ने वहां पर आन्दोलन खड़ा किया था । उस समय हमारा कर्तव्य था कि हम संसार के जनमत को जाग्रत करते, संसार में हम तिब्बत के पक्ष में राय कायम करते और ऐसे देश जो चीन के साम्राज्यवाद में अपने लिए खतरा देखते थे, जो उसकी लपेट में आ सकते थे, उनको एकत्र करते, वे हमारा साथ देते । संसार में अनेकों इस प्रकार के राष्ट्र हैं जो इस खतरे को महसूस करते थे । लेकिन हमने जो एक पुराना नारा अपनाया था—हिन्दी-चीनी भाई भाई, हमने जो पंचशील की सन्धि की थी, उसी कारण हम प्रेम की पींग को बढ़ाते रहे, हमने भारत की जनता को तिब्बत में वास्तविक रूप तथा महत्व से कभी अवगत नहीं कराया । उसके बजाय 1954 में पंचशील की सन्धि करके हम ने उस भूल को दोहराया तथा इसको कानूनी मान्यता दे दी ।

Shri M N. Reddy (Nizamabad): I rise on a point of order. There is no quorum in the House

Mr. Speaker: The bell is being rung ..

Now there is quorum. The hon Member may continue.

श्री श्रीचन्द गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि हमने सब से पहली भूल तब की जब हमने तिब्बत का साथ नहीं दिया । उसके बाद जो कुछ तिब्बत में हुआ चीन का जो अधिकार हुआ था उस को कानूनी मान्यता देकर, पंचशील की मोहर लगा कर, हिमालियन ब्लन्डर की, हिमालय जैसी महान गलती की । पंचशील की अफीम के अन्दर हम ने सारे राष्ट्र की जो चेतना जाग रही थी, उसको सुलाने का प्रयत्न किया, राष्ट्र की उमड़ती देशभक्ति की भावना पर ठण्डा पानी डाल दिया, क्योंकि तिब्बत हम से यह आशा रखता था कि हम उसकी सहायता करेंगे, लेकिन हमने उसको कानूनी मान्यता न देकर, उस पर पंचशील की मोहर लगा कर, इतना बड़ा पाप किया है, इतना बड़ा कुकर्म किया है, कि उसके लिये देश कभी क्षमा नहीं करेगा, न भारत की जनता क्षमा करेगी और न तिब्बत

की जनता क्षमा करेगी, न इस प्रकार के जो संसार के छोटे और दुर्बल राष्ट्र हैं, जो सबल राष्ट्रों की ओर देखा करते हैं कि वे ऐसे समय में सहायता करेंगे, क्षमा करेंगे । यह पंचशील की जो संधि है मैं आज यह कहना चाहता हूं कि इस पंचशील की संधि की धज्जियां स्वयं चीन ने उड़ा दी हैं । इस पंचशील की संधि के अन्दर यह स्वीकार किया गया था कि तिब्बत के जो आन्तरिक मामले हैं उन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा लेकिन आज क्या स्थिति है ? आज तो वहां के नक्शों के अन्दर भी जो पहले चीन का एक आटोनमस राज्य माना जाता था वह भी समाप्त हो गया । आज तिब्बत केवल चीन का एक मात्र प्रान्त बन गया है । उसका केवल एक सूबा बन कर रह गया है । जो आश्वासन तिब्बत को दिये गये, उनको निभाया नहीं गया । भारत और तिब्बत के बीच की सीमा मैक-मोहन रेखा है वह सीमा तो पहले ही शिमला कन्वेंशन की संधि के अनुसार तय हुई थी । भारत चीन की सीमाएं, भारत तिब्बत की सीमा मैकमोहन रेखा स्वीकार की गई थी । क्या मैकमोहन रेखा के मुताबिक चीन ने हमारे साथ व्यवहार किया है ? उस संधि के मुताबिक तो यह करार पाया था कि जो भी भारत के यात्री या व्यापारी है वह ही हिमालय की तराइयों में आ जा सकते हैं । इससे यह बात स्पष्ट थी कि हिमालय के परे का इलाका उनका है और हिमालय के इधर का सारा इलाका हमारा है लेकिन मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि चीन ने आज उस पंचशील की संधि की हर प्रकार से धज्जियां उड़ाई हैं, न उसने अपने आश्वासन को कायम रखा है और न अपने वचन को निभाया है जो उसने तिब्बत को दिया था न जो हमारे साथ उनकी रेखा तय हुई थी उसके ऊपर वह पाबन्द रहा । इसलिए मैं समझता हूं कि हम उसी पुरानी बात की रट लगाते रहें और उस पुरानी संधि के सिद्धान्त को लेकर चलते रहें तो इससे आज काम नहीं चलेगा । आज हमने देख लिया कि किस प्रकार से चीन ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, यहां तक कि जो हमारे वहां पर राजदूत हैं उनके साथ भी अनुचित व्यवहार किया है । हमेशा से चीन का इतिहास विश्वासघात का इतिहास है जैसा कि तिब्बत के साथ में बिलकुल बलात्कार का और भारत के साथ में बिलकुल धोखे का और आघात का इतिहास है । मैं यह समझता हूं कि आज हमें घोषणा करनी चाहिए बड़े बल के साथ घोषणा करनी होगी कि हम तिब्बत की स्वतन्त्रता को स्वीकार करते है । तिब्बत एक स्वतन्त्र राष्ट्र है । वह अपनी आजादी के लिए आज छोटी मात्रा में क्यों न हो प्रयत्नशील हैं हमारे जैसे एक सिद्धान्तवादी आदर्शों पर चलने वाले राष्ट्र को आज उनका साथ देना चाहिए । आज जो दलाई लामा हमारी शरण में आए हुए है उनको वैधानिक शासक स्वीकार कर हमें यह घोषणा करनी चाहिए कि हम संसार के अन्दर तिब्बत की आजादी के लिए पग उठायेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस बात के लिए विवश करेंगे । आज उस को सब प्रकार की ताकत बख्शेंगे । आज उस के पक्ष में संसार के अन्दर जनमत जाग्रत करेंगे और सब को इस बात के लिये तैयार करेंगे कि तिब्बत को एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में खड़ा करने के लिए संसार के बाकी राष्ट्र उसका साथ दें ।

मैं आज यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुरानी बातें नहीं चलेंगी । आज समय की यह मांग है, भारत की सुरक्षा नीति की यह मांग है, भारत के हितों की यह मांग है कि चीन के चंगुल से बचें, चीन के आक्रमण से बचें । आज चीन पूरे तौर पर अपनी तैयारी कर रहा है । आज नहीं, दो साल के बाद या पांच साल के बाद वह फिर आक्रमणकारी के रूप में आयेगा । आज अगर हमें अपने देश की रक्षा करनी है तो उसका एक ही उपाय है कि आज हम अपनी इस बफर स्टेट को फिर से कायम करें। संसार के दूसरे देशों का साथ उस के लिए

[श्री श्रीचन्द गोयल]

लें । उस के लिए सभी आवश्यक कदम उठायें । दुनिया के सब देशों ने जब भी कभी उनकी सुरक्षा का प्रश्न आया है, तो वह युद्ध में कूदे हैं, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इग्लैंड हालैंड देश की रक्षा करने के लिए, बेलजियम की रक्षा करने के लिए, चूंकि उसकी सुरक्षा का उससे सम्बन्ध था, पिछले 100 साल में दो बार वह युद्ध में कूदा । स्वयं चीन 1951 में उत्तर कोरिया के अन्दर जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनायें कोरिया में बढ़ रही थीं, तो अपनी रक्षा के लिए वह उस युद्ध के अन्दर कूदा । इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे हितों की भी यह मांग है कि आज हम अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तिब्बत को स्वतन्त्रता प्राप्त कराने के लिये उसे हर प्रकार की सहायता दें । मैं अन्त में जार्ज गिसबर्गस की "कम्युनिस्ट चाइना ऐंड तिब्बत" से एक कोटेशन हाउस में रख कर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ।

"In short, unless drastic steps are undertaken by New Delhi without delay, the outlook for a successful containment of Red China at the Indian-Tibetan border seems very dim—as dim as the hope once so fondly cherished by most foreign offices that Tibet's impossible landscape with some slight assistance from the Tibettan army would defeat any Chinese invasion. Should such countermeasures not be taken in time or in sufficient number, the repercussions could prove fatal for the free world's survival on the Asian continent. To paraphrase a well-known and undeservedly abused proposition of geopolitics, 'He who holds, Tibet dominates the Himalayan piedmont; he who dominates the Himalayan piedmont threatens the Indian sub-continent; and he who threatens the Indian sub-continent may well have all of South East Asia within his reach and with it, all of Asia.'

Mr. Speaker: Resolution moved:

"This House is of opinion that Dalai Lama should be recognised as the Head of the Emigre Government of Tibet and all facilities and help be extended to him by the Government of India to liberate Tibet from the colonial rule of Communist China".

श्री शिव नारायण (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, यह जो रेजोलूशन हाउस के सामने पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं और उसका क्यों समर्थन करना चाहता हूं वह भी मैं आप की इजाज़त से निवेदन करना चाहूंगा । हम ने जो पंचशील का नारा संसार को दिया था तो उसका अर्थ यही था कि प्रत्येक देश की सुरक्षा की हम जिम्मेदारी लें, उसकी मर्यादा की रक्षा करें और उसकी आजादी की मदद करें । हम स्वतंत्रता का मूल्य और कद्र भली भांति जानते हैं क्योंकि आज हम स्वतंत्र हैं लेकिन अभी थोड़े साल पहले तक हम अंग्रजों के गुलाम थे और उस अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा हम ने अपने त्याग, तपस्या व बलिदान से पाया और हम भारतवासियों ने मिल कर उस गुलामी की जंजीरों को कटवाया । प्रोफेसर रंगा भी उसमें शामिल थे । भारत की आजादी की लड़ाई में सभी भारतवासी शामिल थे और सब लोगों ने मिल कर अपने त्याग व बलिदान से उन अंग्रेज़ों की गुलामी के जूए को उतार फेका । "दिल जले फरियाद करते हैं तो आस्मां हिल उठता है ।" हम वह मुसीबत व कठिनाइयां जो हमें झेलनी पड़ीं उन्हें हम भूलेंगे नहीं । मैं ब्रिटिश वैस्ट इंडीज़ में पैदा हुआ । मैं वहां 14–15 वर्ष रहा लेकिन जब यहां गुलाम हिन्दुस्तान में आजादी की लौ जली और इस देश को गांधी और जवाहरलाल ने सोते से जगाया और उनको आजादी हासिल करने के लिए ललकारा तो सारे देशवासी उनके पीछ कंधे से कंधा

मिला कर खड़े हो गये और हमारे जैसे लोग भी जिनके दिल में आजादी की लगन थी वहां से भाग कर हिन्दुस्तान में आये और हिन्दुस्तान की आजादी के लिए उनकी लीडरशिप में लड़े और कुर्बानी दी। आजादी के दीवाने वहां भी थे और यहां भी थे और हम ने देखा कि इन करोड़ों भारतवासियों की कुर्बानियां रंग लाईं और इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से नजात मिली और देश आजाद हुआ।

यह ठीक ही कहा गया है :

"महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस"।

पड़ोसी पर ज्यादा जिम्मेदारी है। सरदार स्वर्ण सिंह से मैं कहना चाहता हूं कि भारत तिब्बत का पड़ोसी है और आप सरदार हो, सिंह हो और इसलिए आप के डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए जो भूल हम पहले कर चुके हैं वह हम फिर न करें। हम फिर से तिब्बत सम्बन्धी नीति पर विचार करें और उस भूल को समाप्त करें और मैं समझता हूं कि इससे सरदार पटेल की आत्मा को शांति मिलेगी। आज भी हमारे देश में ऐसे लाल मौजूद हैं जो अपनी भूल को ठीक कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरदार साहब तो उस भूल को ठीक करेंगे ही। आज काले और गोरे लोगों के ब्लाकों में एक लड़ाई है और इसलिए यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है। हम तो चाहते हैं कि जिस तरह से श्री राम ने विभीषण को शरण दी और रावण पर विजय पाने के पश्चात् लंका का राज्य श्री राम ने विभीषण को सौंप दिया वैसे ही दलाई लामा और अन्य तिब्बती लामा आज हमारी शरण में हैं और हमें अपने शरणागतों की श्री राम के समान रक्षा करनी चाहिए व उनकी मदद करनी चाहिए और जिस प्रकार लंका का राज्य पुनः विभीषण को श्री राम ने दिलवाया उसी तरह मैं चाहूंगा कि हम भारतवासी तैयार होकर उनकी खोई हुई आजादी को पुनः वापिस दिलायें। दलाई लामा को विभीषण के समान तिब्बत के ऊपर उनका खोया हुआ अधिकार पुनः वापिस दिलवायें। ऐसा किया जायेगा तभी चीन की बढ़ती हुई ज्वाला, उसका राक्षसपन, मिट सकेगा। इसको मिटाने में हम आप के सहायक होंगे, मददगार होंगे।

17 hrs.

मैं माफी चाहता हूं यह कहने के लिये कि हमारे पुराने राजनीतिज्ञों ने बड़ी भूल की है। उस भूल का निराकरण आप को करना चाहिये। कहे कबीर जब ही चेता तबै सही। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। अगर बेटा लायक हो और बाप की गलतियों को सुधार दे तो वह क्षम्य होता है। अगर हम ऐसा कर सकें तो इतिहास में हमारी कीर्ति अमर होगी। पिछले दिन मैं इस देश के डिफेन्स की बात कर रहा था तब कहा था कि हमारे सरदार साहब बड़ी हस्ती हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने बड़ी कुर्बानी की। वह ताशकन्द में मरे। वहां पर उन के साथ हमारे डिफेन्स मिनिस्टर और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मौजूद थे। हिन्दुस्तान के बच्चे बच्चे के दिल के अन्दर वह दर्दनाक चित्र आज भी जलन पैदा करता है, वह दुःख अभी भी बाकी है। वह जल्दी मिट भी नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज भारत यह तय करे कि हम तिब्बत के साथ भलमन्साहत का व्यवहार करें, उसकी मदद करें, धन, जन, बल हर तरह से उसकी मदद करें।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

Shri D. N. Patodia (Jalore): Today, the House is reminded of a dark moment in the recent history, 17 years ago, on 7th October, 1950 when while the Tibetan delegation was negotiating with the Chinese ambassador in New Delhi; the Chinese on the other hand invaded Tibet. On that day a process of extermination of the

[Shri D. N. Patodia]

race, religion tradition and the nation of Tibet started. That process still continues. Tibetans had been dispossessed of their property; they were left with no job, they were not provided with adequate food and they were brought to the brink of death sometimes The most heinous crime that the Chinese have committed is that they have sterilised thousands of men and women in Tibet so that the race of Tibetans is extinguised from the earth. They have made every attempt to wipe out the religion of Tibet. Monastaries had been destroyed or converted into police headquarters of the Chinese police; the monks had been murdered or arrested or thrown out. This is an event of unparalled significance in the history of the world when one nation is trying to wipe out another nation, its race and religion. Genocide is being practised. It is equally shameful and equally unparallelled in the history of the world—the attitude of India. We had been instrumental and we had been a party to the domination of Tibet by China. Our attitude towards a neighbouring country, Tibet, will be remembered long. The neighbour trusted us and depended on us. There were close religious and cultural ties between India and Tibet. We have betrayed them; this is the reflection of our weak policy in order to please China who are very powerful, we forgot all our obligations and we forgot the old traditions of 2500 years ago. 2500 years back one person belonging to the kingdom of Kaushal went from India and established the kingdom of Tibet and from that day the historical and traditional ties between Tibet and India continued in addition to the religious, cultural and philosophical ties. We have forgotten all that. But now we realise what mistake we have done. Now we understand that by giving over Tibet to China we have surrendered the sovereignty not only of Tibet but we have made the biggest blunder which we could have made from the defence point of view. Prior to that, the launching ground of China from which they could have attacked our country was thousands of miles away, but now, after having given over Tibet, they are on our head, and our long borders are exposed to China day in and day out. This is the condition in which we are placed today, and Shri Lal Bahadur Shastri, our late Prime Minister, had admitted it in the course of one of his speeches on this point He said that, "China's object in annexing Tibet is clear today, it was to use Tibet as a base for launching an attack on India." Therefore, it explains that possibly the germs of the Chinese attack on our land in 1962 were sown as early as in 1950, when for the first time, the Chinese attacked Tibet

Now, I will come to the constitutional side of it. Various treaties, to which my friend Mr Goel has already, referred, were entered into sometimes between Britain and China, sometimes between China and Tibet and sometimes between Tibet and Britain All the same, until 1954, until the one treaty that was signed with our late Prime Minister Jawaharlal Nehru, in all the treaties, the suzerainty and sovereignty of Tibet was never questioned. The Chinese stayed in Tibet only as some sort of a privileged person, enjoying certain rights without in anyway affecting the autonomous status of Tibet, or without affecting the rights of Tibet. This could be proved by two or three events.

In 1876, in spite of the Chinese desire, the Tibetans did not permit the British Mission to visit Tibet. Again, during the World War II, as it is known to all of you, Tibet did not allow war materials to go to China via Tibet. These two illustrations are clear to show that the sovereignty was not only never doubted, but it was accepted and agreed to even by the

Chinese. Even against Chinese desire, Tibet could take action and protest, because, after all, a sovereign nation is always within its rights to act as it likes.

Coming to the treaty of 1951, in this treaty also, the sovereign rights of the Tibetans were recognised. In 1951, it was an agreement between China and Tibet, in which India was not a party, and, the autonomy and the sovereign rights of Tibet were recognised But for the first time, in 1954, when India was a party to it, we were responsible for the words put in the agreement We for the first time accepted the sovereignty and suzerainty of China over Tibet by saying that Tibet is a part of China After that, this chain started. After that history took a new turn, and China started to create trouble with the ultimate motive of attacking India.

But there was one safeguard put into the treaty of 1954 It was that there would be some corresponding action by the Chinese also: they will give full autonomy rights to Tibet; that they will not interfere with the internal affairs, with their religion, their way of life and with their system of government These were the basic agreements, which were arrived at, to which China, India and Tibet were a party But the Chinese never honoured this agreement. Possibly, even before the agreement was signed, China started violating it. Therefore, whether it is an international agreement or a national agreement or in whatever form it is, an agreement can always be only bilateral. It cannot be unilateral. Therefore, this agreement stands as a dead agreement. It has no validity, and if the Chinese have decided to violate it, we must also search our hearts and give a different thought to it. A very thorough enquiry in this connection was made by the enquiry committee set up by the International Commission of Jurists. I will read a passage from their report:

> "Throughout the period 1912 to 1950, the Government of Tibet exercised exclusive authority in domestic affairs within its territory. It successfully defended its territory against attack under the colour of a claim to soverignty and *vis-a-vis* the Republic of China no act was committed or declaration made that compromised its internal independenc ."

This is the unanimous opinion given by the jurists That process which started in 1950 by the attack of China still continues. Things have not improved. All loyal Tibetans have been driven away and even massacred. The Dalai Lama, the spiritual Head of Tibet, fled to India with his followers. He does not have any means to defend his country. He depended upon India, but India has betrayed him, in whatever form it is. Therefore, it is time for us to think of the whole problem again

We should look at it from three different angles Firstly, from our defence point of view, it is necessary that Tibet is given independence and permitted to develop its own religion and way of life. Secondly, we should look at it from the humanitarian point of view. On humanitarian grounds, the people of Tibet should be permitted to live according to their own religion and way of life. They should have freedom of speech and freedom of living. Then we should look at it according to old traditions of history. I hope taking into consideration all these factors, wisdom will dawn upon the Government of India and they will recognise the Government of the Dalai Lama and denounce the treaty of 1954. We should render all possible help to the Dalai Lama and his followers to form a stable Government in Tibet. We should also withdraw the support we are giving in the United Nations for the admission of China. Relations with China must be broken. There is no reason why in spite of all that has happened, we should continue pampering them.

With these words, I support the resolution.

Shri J. K. Choudhury (Tripura West): Sir, it has been said that history has a nemesis for every sin, and the history of India since independence is replete with sins like the one we committed in the matter of Tibet. Of course, 20 years is not a very long time in terms of history, particularly in matters of cause and effect. Yet, it must be admitted that the 1954 treaty brought ultimately the Chinese invasion on us.

My predecessors speaking on this resolution have given many facts. To begin with, India had inherited certain rights from the British like postal connections, trade relations, keeping a small section of our military personnel there and such others. But we had also a very close connection with that country for thousands of years—cultural, historical and even religious. In one sense, the people of the entire northern zone of India in the southern Himalayas have very intimate relations with the Tibetans—ethnically and also in matters of religion and culture.

17.15 hrs.

[SHRI G. S. DHILLON *in the Chair*]

But, what did we do? As soon as the Chinese came into power after the independence of India, they attacked Tibet in 1950. We did not say anything at that time. In 1954, we were misled into believing that Tibet would be treated as a free autonomous region of China and entered into treaty with that country. They called it "autonomous religion of China"—that is the wording they used. They had to use it because in the 1914 Simla Treaty, which the Government of India has shown in maps and in many booklets they published, particularly of this *"Chinese Menace"*, the Chinese agreed to Tibet signing that treaty along with India as a separate power. It appears that India signed it or, rather, the British on behalf of India signed it and Tibet also signed it along with China.

And what did China do? She repudiated her signature in respect of *outer* Tibet soon after 1914. She did not repudiate the 1914 demarcation treaty held at Simla and signed by her representative, for the whole of Tibet. It was only the inner line that she agreed to respect. But for the outer line she had her reservations.

If even the inner line of Tibet remained under the Tibetan Government undisturbed by the Chinese that would act as a buffer State for India just as Outer Mongolia acts as a buffer State to Russia. But what happened? Throughout history it is a commonplace of foreign relations and protection of a country that everybody wants to keep a buffer, between a country and another which is at least as strong as it is. The British Government fought three wars with the Afghans, but even after defeating Afghanistan three times she used to pay subsidy to the Afghans because at that time it was the Russian menace that the Britishers in India feared most. In those days of British Empire international laws were regarded with much more sanctity than at present, So they thought the Russians, if they wanted to attack India in the North-West Frontier, would have to come through Afghanistan and they could not do it without breaking the international law. That law no longer holds good. The Germans in 1914 and Hitler later finished that by attacking Belgium before attacking France.

The MacMahon line was recognised in the 1914 treaty which was signed at Simla. It continued like that till 1954 when the Communist China's authority was recognised by India. Before that, of course, after the overthrow of the Manchu Dynasty by Sun Yat Sen in 1912. China was growing in power with many war lords in different parts of it. She was not a compact State even then, sprawling over 36-lakh square miles as now, coming just over our head in the Himalayas as she did in 1962. We gave away, we bartered away the liberty of Tibet and also our defence.

We paved the way for China to come up to the Himalayas and just below the passes on the other side to have her military installations and massing of troops and building of roads and other preparations. That paved the way for the 1962 attack on India. We now find ourselves in a difficult and tight corner. We are now terribly afraid, because, I have heard it said in this very House in connection with the embassy troubles that we desist from retaliation lest China should invade us again!

What were we afraid of in taking retaliatory measures against the Chinese Embassy here? An invasion from China? Well, if it comes really to that, that China will invade us as soon as we want to assert our rights, let her do so so. We should be determined either to conquer or to fall. It does not matter if even a single Indian is not spared the sword. That should be our attitude, though that may be called an irresponsible attitude.

Throughout the history of mighty nations there has been an element of irresponsibility in great deeds and events of their life. The Greeks at Thermopylae were irresponsible in fighting with only 300 men against the Persian hordes. Rana Pratap was irresponsible in fighting against the Mughal Empire with his small army of Bhils and Kols. Even as near as three weeks ago Israel with two millions of them fought against 100 millions of Arabs. You might call all this irresponsible. But why can't we, 500 million Indians, be determined to fight China, if it comes to that? We have to fight China on moral and patriotic grounds and not allow her to cross over the Himalayas even for an inch. We shall have to do it, come what may, some day or other. There is no question of responsibility or irresponsibility in that.

So, without in any way being inhibited by China or her strength, by her atom bombs or her hydrogen bombs, we ought to see to it that, what we committed as a sin against the Tibetans, and what the Dalai Lama, has mentioned in his autobiography does not go to the credit of India—that chapter of shame is redeemed. So, we ought to support his right to set up an emigre Government of Tibet in India and also we ought to take up her case in the United Nations.

श्री जार्ज फर्नेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, इस बात में कोई शक नहीं है कि तिब्बत के बारे में जो नीति इस सरकार ने विगत पन्द्रह बीस वर्षों में अपनायी थी वही खास वजह है कि आज चीन से इस मुल्क को सब से बड़ा खतरा दिखाई देता है। अगर चीन और तिब्बत वाले ऐग्रीमेंट को रोकने में मदद करते उस वक्त तो यह बिलकुल नामुमकिन था कि आज चीन से किसी किस्म का खतरा या खास तौर पर जो खतरा आज हमें दिखाई देता है वह हम लोगों पर आ जाता। मगर सिर्फ चीन के ही बारे में इस तिब्बत नीति ने हमें नहीं नुकसान पहुंचाया बल्कि हिमालय के आसपास के तमाम मुल्कों में हिन्दुस्तान की तस्वीर को बिलकुल ही उतार देने का काम इस तिब्बत नीति ने की। नेपाल, भूटान और सिक्किम जैसे देश भी आज अगर हिन्दुस्तान से दूर हट रहे हैं, सिक्किम जैसा छोटा सा देश जो एक ढंग से इसी देश का हिस्सा करके माना जाता है, अगर वह भी आज अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाने के प्रयास में लग रहा हो तो उस का मूल कारण अध्यक्ष महोदय, आप को इसी में दिखाई देगा जो तिब्बत के बारे में हम लोगों ने बिलकुल कमजोरी की नीति को कई वर्षों से पहले अपनाया। हम यह समझते हैं कि जो गलतियां और जो भूलें इस तिब्बत की नीति के बारे में आज तक हम लोगों ने की उन को बिलकुल सुधारने का काम अब करना चाहिए। इस बात में पड़ जाने से कोई मतलब नहीं कि तिब्बत की आजादी की या तिब्बत के खास अस्तित्व की बात को अगर हिन्दुस्तान ने मान लिया तो फिर हम लोगों पर कोई ऐसा आरोप लगाया जायेगा कि यह

[श्री जार्ज फर्नेन्डीज़]

साम्राज्यवादियों के बगलबच्चे हैं या अमरीकी दलाल हैं या अंग्रेजों के दलाल हैं। इस किस्म के आरोप लगाये जाने की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मैंने कल ही पढ़ा था कि चीन ने जो अणुबम विस्फोट किया उस के ऊपर अपने विचारों को प्रकट करते हुए रूसी सरकार के प्रवक्ताओं ने बताया कि चीन के लोग अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाने के काम में लगे हुए है। तो विस्तारवाद और साम्राज्यवाद इसके बारे मे आज अगर किसी भी एक मुल्क के ऊपर खास तौर से आरोप करने जैसी परिस्थिति आयी है रूस के बयान में तो वह चीन है असल म बहुत ही कटु शब्द रूस के प्रवक्ताओं ने इस्तमाल किए हैं जो कल ही मुझे पढने को मिले। उस मे वह कहते है :

"The feudal rulers of China are on a expansionist spree."

यह अमरीकी लोगो का कहना नही है, यह साम्राज्यवादियो का कहना नही है। यह रूस के कम्युनिस्ट रूस के सरकार के प्रवक्ताओ का कहना है तो इस लिए हमारी सरकार को, इस मुल्क की सरकार को इस चिन्ता मे पड़ने की कोई वजह नही है कि हम लोगों के ऊपर कोई आरोप करेगा कि हम साम्राज्यवादियों के दलाल है। मैं तो असल मे यह कहना चाहता हूं कि इस तिब्बत की नीति के बारे मे पुनर्विचार करते हुए, पहले की हुई गलतियों को दुरुस्त करते हुए अगर सब से ज्यादा किसी से भी सलाह मशविरा किसी को करना हो तो वह रूस के साथ ही करना चाहिए। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, आज चीन का सब से ज्यादा किसी से भी झंझट और किसी से भी लड़ाई है तो एक तरफ तो हिन्दुस्तान के साथ है और दूसरी तरफ वह रूस के साथ है, कई चीजों को लेकर है, आउटर मंगोलिया के सवाल को लेकर है, साइबेरिया के सवाल को लेकर है, कजाकिस्तान के सवाल को लेकर है और चीन की सीमा हिन्दुस्तान के साथ जितनी है उस से ज्यादा लम्बी सीमा आज रूस के साथ है। हिन्दुस्तान के साथ चीन का जितनी बार संघर्ष हुआ, और बड़ी लड़ाई तो हमीं लोगों से की लेकिन छोटे मोटे बन्दूक चलाने वाले गोली चलाने वाले तो संघर्ष होते है वह रूस और चीन के बीच में विगत दस वर्षों में जितनी बार हुए हैं, उतनी बार हिन्दुस्तान और चीन के बीच मे नही हुए हैं अध्यक्ष महोदय यह असलियत है और असल मे इस देश के हित की दृष्टि से यह बिलकुल ठीक होगा कि रूस के साथ इस चीनी नीति के बारे मे और खास तौर पर तिब्बत नीति के बारे में हम लोग जरूर सलाह मशविरा करने का कार्य करे और किस ढंग से उन की मदद इस की हुई गलती को दुरुस्त करने मे मिल सकती है उस के बारे म हम लोग जरूर सोचे।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी समझदार व्यक्ति को यह समझाने मे मुश्किल न होगी कि तिब्बत एक आजाद देश रहा है सैकड़ों नही हजारों वर्ष के इतिहास मे वह एक आजाद देश रहा है और अगर रिश्तों के मामले पर ही बहस चलानी हो तो तिब्बत के रिश्ते हिन्दुस्तान के साथ ज्यादा रहे है। भाषा का मामला लीजिये, लिपि का मामला लीजिए, उन के मजहब का मामला लीजिए, तिब्बत से जो नदियां आती हैं उन नदियो का प्रवाह किस तरफ जाता है, चीन की तरफ जाता है या हिन्दुस्तान की तरफ जाता है, इन तमाम बातो को देखिये, तिब्बत के इतिहास को देखिए, संस्कृति को देखिए, चाहे जो कसौटी लगाने का काम करिए, हर कसौटी से आप को यही देखने को मिलेगा कि एक तो तिब्बत आजाद मुल्क रहा है और अगर तिब्बत का ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक या धार्मिक, भाषा या किसी भी मामले मे कोई भी सम्बन्ध था तो वह हिन्दुस्तान के साथ बराबर रहा है, चीन के साथ कभी नही रहा। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, रूस को समझाना या और किसी भी मुल्क के लोगों को समझाना, किसी

भी समझदार व्यक्ति को समझाना कि तिब्बत एक आजाद मुल्क है और उस की आजादी के लिए हमें प्रयास करना होगा, इस में कोई भी तकलीफ होगी ऐसा मैं तो बिलकुल नहीं समझता और इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज जब मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मैं सरकार से कहूंगा कि एक तरफ दलाई लामा के बारे में आज तक जो हम लोगों की नीति रही है वह बिलकुल ही गलत रही है। चन्द दिनों पहले यहां पर प्रश्न आया था और उस का उत्तर देते हुए मंत्री जी ने कहा कि उन के मुंह पर हम लोगों ने कोई ताला नहीं लगाया है। अब मैं शाब्दिक झंझट में नहीं पड़ना चाहता। हम किसी के मुंह पर ताला नहीं लगाते। लेकिन अपने देश के लोगों के बारे में, अपने देश की परिस्थिति के बारे में और अपने देश की आजादी के लिए दलाई लामा आज हिन्दुस्तान के अन्दर न कुछ कर सकते हैं, न कुछ बोल सकते हैं, इसलिए उन को यह आजादी देनी चाहिए कि वह अपने मुल्क की आजादी के बारे में बोलें। हिन्दुस्तान में शरणागत होने के पहले अपने मुल्क में जिस तरीके से कामकाज को वह चलाते थे, मैं यह नहीं कहता कि उन को उसी ढंग से चलाने को कहा जाय, प्रजातंत्र को तिब्बत के अन्दर लाना, यह दलाई लामा के हाथ में कहां तक होगा, यह नहीं कहा जा सकता, वह तो हिन्दुस्तान के लोगों को करना होगा लेकिन प्रजातांत्रिक तरीके से वह अपने देश के काम को अपने हाथ में लें इस दृष्टि से जो भी मदद उन को देनी चाहिए वह हम दें। दूसरे, जितने भी शरणार्थी लोग हैं वह बेकार हैं, खम्पा लोग हैं, और दूसरे हैं जो सड़कों पर पड़े रहते हैं, गोरखपुर जैसे इलाकों में जाइए तो पहाड़ों पर, जंगलों में या सड़कों पर लोग सड़ रहे हैं। सभापति महोदय, उन को जहां तहां भी नौकरी इत्यादि में लगाने का काम हो सकता है, वह जरूर किया जाय लेकिन साथ ही साथ उन को अपने मुल्क में वापस जाना है उन को अपने मुल्क को वापस लेना है, यह भावना उन के मन में निर्माण करने के लिये उन को प्रशिक्षण दिया जाय। वह प्रशिक्षण चाहे बन्दूकवाला प्रशिक्षण हो या सांस्कृतिक प्रशिक्षण हो या अन्य किसी किस्म का प्रशिक्षण हो—यह दलाई लामा से पूछा जाय मगर उनके मन में यह भावना जरूर रहनी चाहिये कि हमारा मुल्क तिब्बत है, आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों, हम जरूर अपने मुल्क को वापस जाने वाले हैं— यह भावना उन के मन में निर्माण की जाय।

तीसरी बात, इस मसले को केवल हिन्दुस्तान में बहस का मसला न बनाते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मसला बनाना चाहिये। मैंने पहले कहा है कि रूस के साथ हम को इस मसले पर बहस चलानी चाहिये, लेकिन उस के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी तिब्बत के मामले को हमेशा उठाते रहना चाहिये। इस मामले पर अनिच्छुक रहने की नीति हमें छोड़ देनी चाहिये। चौथे, ये जितने हिमालय के आसपास के देश हैं— सिक्किम में झंझट चला है, मैं उस पर इस समय ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि वह बहुत गम्भीर मामला है—भूटान है, नेपाल है, जहां प्रजातन्त्र खत्म हुआ है— जिस राजा को वहां का राजा बनाने के लिये, राणाशाही से मुक्त करने के लिये हर किस्म की सहायता हम ने की, उस राजा को मुक्त करने के लिये हमारे हजारों नौजवान मारे गए, फिर उसी किस्म की राणाशाही वहां की जनता पर चल रही है, लेकिन इस में भी दोष हमी लोगों का है, क्योंकि इस इलाके में प्रजातन्त्र के किसी आन्दोलन को, किसी भी जन आन्दोलन को, न हिन्दुस्तान से स्फूर्ति मिलती है और न सहायता मिलती है, वह स्फूर्ति और वह मदद हमें हिमालय के आसपास के इन तमाम मुल्कों में प्रजातन्त्र लाने के लिये देनी चाहिये।

आखरी बात, जिस पर मंत्री महोदय जरा विचार करें। कई दिन से एक बहस

[श्री जार्ज फर्नेन्डीज]

चल रही है कि चीनी सरकार की ओर से कोई ऐसा सुझाव आया था कि तिब्बत के बारे में अकसाई चीन हमें दे दो तो दूसरी तरफ की जमीन के बारे में हम सहायता करने के लिये तैयार हैं । ऐसा कोई सुझाव पं० पंत के पास आया था, लेकिन उन्होंने उस को इन्कार कर दिया । ऐसा ही कुछ जिक्र पिछले दिनों राज्य-सभा में भी आया था, उस पर स्वर्गीय पंत जी के सुपुत्र ने कुछ अलग से कल बयान दिया है । उन के पास कौन सा सुझाव आया था, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा एक अनुभव है, जिसे मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिये रखना चाहता हूं । इसी किस्म की एक बात डा० राम मनोहर लोहिया साहब ने इसी सदन में रखी थी—यह मई, 1965 का किस्सा है । मैं किसी काम से जेनेवा गया था वहां जूरामाउन्टेन्ज की पहाड़ियों में एडगर स्नो साहब से मुलाकात हुई थी जो पश्चिमी दुनिया के और चीन के सब से बड़े दोस्त हैं । व्यक्तिगत तौर पर उन से कई घन्टे तक हमारी बातचीत हुई, मुलाकात हुई । एडगर स्नो साहब चीन के तमाम नेताओं के दोस्त हैं 30 वर्ष चीन रह चुके हैं तथा दो-तीन साल पहले चीन से आकर वह कई नई किताबें लिख रहे हैं । पांच-छः साल पहले उन्होंने "रेड स्टार ओवर चाइना" लिखी थी और अब "दी अदर साइड आफ दी रिवर" लिखी है । जब मेरी उन से बातचीत चली, तो एक बात उन्होंने मुझ से पूछी—क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि चीन से लड़ लड़ कर जो जमीन आपकी गई है, वह उस से हासिल कर लोगे । मैंने उन से कहा कि इतिहास तो कभी भी चुप नहीं बैठा रहता है, इतिहास तो चलता रहता है। कब क्या हो, कोई नहीं बोल सकता है । इस वक्त फिर बन्दूक चले तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, हो सकता है कि साल लगे, दो साल लगे, हो सकता है कि हम अपनी खोई हुई जमीन को फिर हासिल कर लें । तब वह बोले कि लड़ाई करने से यह काम नहीं होगा, तिब्बत आज चीन के हाथ में है, उसके साथ लड़कर कामयाबी नहीं मिलेगी, तुम्हें दोस्ती से रहना चाहिये । मैंने कहा—चीन और हिन्दुस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती है । तब वह बोले—कभी कोशिश की है ? मैंने कहा—देखिये साहब, हम तो न सरकार में हैं और न सरकारी दल से कोई रिश्ता है । तब उन्होंने बताया कि चीन अकसाई, चीन कभी नहीं छोड़ेगा, उस के लिये उस को चाहे कितनी कुरबानी करनी पड़े, लेकिन वह उस को नहीं छोड़ेगा, मगर जो पूर्ववाहिनी ब्रह्मपुत्र है—वह तुम्हारा और चीन की सीमा हो सकती है । तब मैंने उन से पूछा—आपको किस ने यह बात बताई, क्योंकि वे चू-एन-लाई और माओत्सेतुंग साहब से भी मिले थे । उन्होंने कहा कि यह हम से मत पूछो । हम से मत पूछिये कि मैं किस अधिकार से बोल रहा हूं, लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि चीन अकसाई-चीन को कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन पूर्ववाहिनी ब्रह्मपुत्र हिन्दुस्तान और चीन की सीमा हो सकती है । जिसमें हजारों वर्ग मील जमीन मिलेगी और हमारा संरक्षण का मामला भी जम जायेगा । मैंने इस बात को लौटने के बाद डा० लोहिया साहब को कहा और उन्होंने इस मसले को इस सदन में छेड़ा । पता नहीं सरकार ने इस पर कुछ सोचा या नहीं, मैंने सिर्फ जानकारी के लिये ही इस बात को यहां पर रखा है ।

तिब्बत के बारे में जब हम यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान के साथ उस का क्या रिश्ता है तो मनसर गांव का उदाहरण दिया जाता है। हिन्दुस्तान और तिब्बत की सीमा से तिब्बत के 200 मील अन्दर का यह गांव चीनी आक्रमण होने तक हिन्दुस्तान की सरकार को अपना रेवेन्यू टैक्स देता था । 10-12 साल पहले तक यह मामला चलता रहा था, परन्तु इस सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी । डा० राम मनोहर लोहिया साहब ने इसकी खोज की और हिन्दुस्तान के सामने रखा. .

श्री शशि भूषण वाजपेयी (खारगोन) : यह लगान शायद राम मनोहर लोहिया साहब को देते थे ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मगर आपकी सरकार को यह भी मालूम नहीं था । जवाहर लाल नेहरू जी ने डा० राम मनोहर लोहिया से विनती की कि मेहरबानी कर के वह सुबूत हमारे हाथ मे दे दो, तब लोहिया जी ने कहा कि तुम खोज करो और तब वह निकला, तब उन को मालूम हुआ कि लोहिया साहब ने जो कहा था वह ठीक था ; जवाहर लाल जी का सोचना गलत था, देश के बारे में कुछ सीखने की कोशिश कीजिये ।

यह असलियत हम ने एडगर साहब को बताई तो वे बोले कि अगर इस खोज को मुझे भेज सकोगे तो मुझे भेज देना, क्योंकि हम भी इस बात को नहीं जानते थे । बाद में वह किताब डाक्टर साहब की छपी तब वह एडगर साहब को भेजी । उन के साथ कभी कभी पत्र-व्यवहार चलता है, लेकिन वह व्यक्तिगत तौर पर चलता है। यह मैंने मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये सदन के सामने प्रस्तुत किया है । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का पूरा पूरा समर्थन करता हूं ।

Shri K. R. Ganesh (Andaman and Nicobar Islands): I rise to oppose this Resolution which has been moved as a Private Member Resolution. We have to face certain realities of the situation It is a fact that India has recognised the suzerainty of China over Tibet We know what is happening in China today. We also know that the Chinese have betrayed the understanding which they gave to ou Prime Minister that they would res peot the autonomy of Tibet Chini today has become an aberration it world politics. It is not that China is having a hostile attitude, a warlike attitude, towards our country alone, but China is having the same war-like and hostile attitude towards a number of other countries also, including the Soviet Union, which has been the best friend of China and without whose help, the Chinese Revalution could never have succeeded. Therefore, we are faced with a country which has placed the world in such a quandary that all the assessment that all the world leaders had about the Revolution of China has been falsified. It has become a habit in this House that, whenever any matter is raised, whe'her it is of Tibet or of West Asia or of any other matter, the entire gamut of the foreign policy of the Indian Government is attacked; the object is not to give help to the Tibetans As the Government of India found that the human rights in Tibet were being denied to the Tibetan people by the Chinese Government, they raised this question as a human rights question in the United Nations. But the object of the hon Mover and many other Members on the other side of the House is to attack the entire foreign policy of this country and to show to the people that the foreign policy of this country has failed. We know that there is a large body of opinion in this country which feels and which is convienced that the foreign policy followed by the Indian Government under the leadership of Jawaharlal Nehru was the correct foreign policy, was a policy in the interests of the country, and in the world in which we are living, we could not have followed any other foreign policy

Shri Ranga: Question.

Shri K. R. Ganesh: They talk of buffer States This talk of buffer States in the world of 1967 is to take us back to the 17th and 18th centuries They also say that this buffer State business has brought about wars in the world And yet they want us to maintain Tibet as a buffer State.

We know that a larger area of our country which we claim as our own area is under the occupation of China. It is a herculean task for the Indian Government and the Indian people to eliminate Chinese influence and to liberate that area from Chinese influence and Chinese occupation. If we recognise the Dalai Lama and if we allow him to set up an amigre government in India, and if we take the issue of Tibet to the UN and help the

[Shri K. R Ganesh]

Dalai Lama, then we would be opening a flood-gate for every foreign country to interfere in our own internal affairs

Shri Ranga: Oh!

Shri K. R. Ganesh: I am surprised that such a senior Member of our national movement could be so synical about the remark that I have just made We are having the NEFA problem, we are having the problem of Nagaland; we are also having the Kashmir problem Day in and day out, our friends here go on pointing out that the Chinese are interfering in NEFA and Nagaland and that the Pakistanis and the Chinese are in collusion as far as Kashmir is concerned

Having once recognised the suzerainty of China over Tibet which is historical, because no Chinese Government has ever disclaimed it and no Chinese government has ever been a party to any treaty in the world under which they have forsworn Tibet we shall be opening the floodgate of interference in our own internal affairs by other countries if we act on the lines suggested in this resolution

We know that the Chinese Government is following an expansionist policy, and we know that they are doing so not only towards this country but also towards the Soviet Union We know that the Chinese Government has become isolated from every other country in the world During the last two days we have read in the newspapers that what has happened in India has happened in Burma also

Therefore, in this situation in which we are placed, to accept the resolution will be to invite disaster as far as this country is concerned

The resolution and also the speeches made presuppose that Tibet is going to be our buffer to ensure the safety and security of this country

I submit that whatever may be our present trouble with China—I know I may not be carrying quite a substantial section of this House with me in saying this . . .

श्री रवि राय (पुरी) इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य इन में आप के साथ नहीं है। श्री शिव नारायण भी नहीं है।

Shri K. R Ganesh अकेला सा हूं।
Whatever that may be that could be decided He does not after all represent many people

Whatever may be our present trouble with China, whatever may be the postures, the very dangerous postures of the Chinese Government, we must not forget that after all, China is a country with one of the largest mass of people in the world and whether it is today tomorrow or the day after without sacrificing our own independence without sacrificing our own sovereignty, without sacrificing the democratic structure we have given to ourselves we have to come to some understanding with China There is no other way because here are two countries which represent the largest section of humanity, here are two countries which have got common historical links, here are two countries which are neighbours and here are two neighbours who could have forced the entire world into a direction which because of the betrayal of the Chinese Government China and the Chinese leadership could not be brought about with the result that imperialism is on the offensive in West Asia and other regions of the world

Therefore, I submit that this Resolution aimed at helping Tibet by recognising the Dalai Lama and by setting up an emigre government here is not in the interest of this country This country has helped the Tibetan refugees in all possible ways This country has given asylum to the Dalai Lama This country is raising the question of the murder of human

rights in Tibet in the UN. There is no other policy in the interest of the country than the one which has been pursued by the Government up till now.

Shri asudevan Nair (Permade): The Mover of the Resolution and some other hon. Members who have supported him have advanced a strange logic. They say: China misbehaves, so India also should misbehave, China interferes in the internal affairs of other countries, so India should also do the same; China is warlike, so India also should be warlike. This is the essence of the logic that has been advanced by the Mover and many others including Shri Sheo Narain who is a misguided Member

Shri Sheo Narain: No, no; he is misguided.

Shri Vasudevan Nair: Some Members have chosen to relate cock and bull stories about what has happened or is happening in Tibet I should like to make it very clear that it is common knowledge that the Chinese leadership is following a policy detrimental to the interest world peace, which is detrimental to the interest of friendship between peoples, especially peoples of Asia and Africa, which is detrimental to the interests of the people of even China herself. There is no doubt about it But my friend Mr. Goel should not imagine that this is an unchangeable policy and that this is an eternal phase We do not subscribe to that theory Even after the communist party came to power in 1948, there was a certain period in the history of China when they were pursuing an entirely different policy. Let us not forget that. This is a particular phase in the history of a great country and a great people when unfortunately the leadership is pursuing a very different, wrong and detrimental policy as regards their people and their country and the entire world. Keeping that in mind, we must be very careful in pursuing our own policy. India has been following more or less a correct policy as far as Tibet is concerned, all these years. Of course some people were pressurising India to alter its policy.. . (*Interruptions*). I should like to emphasise the necessity for continuing that policy There is the principle of non-interference in the internal affairs of another country. My friend there very rightly pointed out that there were black spots for every country and there are problems for every country. So, if one country begins to interfere in the internal affairs of another, there is no end to it Simply because the Chinese are doing a very wrong thing let us not imitate them In our own interest it is very wrong to suggest that we should have an emigre government on the soil of India which will create 101 problems It is wrong to suggest that we should help them to conquer Tibet About Tibet being a buffer State and all that, my friends are depending upon British history and the evidence of British imperialists, who played the dirty game for centuries together all over Asia. Let us not forget all that and now for the sake of convenience depend upon evidence supplied by the British.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : तिब्बत के मामले मे मैं रूस को मानने के लिये तैयार हू ।

Shri Vasudevan Nair: My friend Mr Fernandes was very much dependent on the Soviet Union. He said that we should consult the Soviet Union He should know that the Soviet Union is not reciprocating what China does He forgets that they show such restraint in the face of grave provocations (*Interruptions*) Let us agree to disagree

Thirdly, these friends want to prop up the institution of the Dalai Lama. With all respect to the personality of the person, it is as an institution the most rotten institution, the most backward and reactionary and inhuman institution. Such an institution is to be supported by a country which professes to be progressive?

Sir, it is not strange, it is not surprising, that in India, those who want

[Shri Vasudevan Nair]

to support and prop up this Dalai Lama are those very people who want to maintain the old order, the reactionary order, the feudal order, and all those superstitions in this country. It is not strange. *(Interruption)*. I can understand the Jan Sangh; I can understand the Swatantra party; I can understand such reactionary parties running to the rescue of the Dalai Lama, but let not this country put its camp on behalf of such a reactionary institution.

So, from these three points of view, it is detrimental for us to change our policy, which was tested all these years. Because of pressure, I know the Government has deviated: I am referring to the recent position taken by the Government even on the question of human rights, I may point out that that is bcause of pressure. Unfortunately, recently, some statements made by the External Affairs Minister have given the impression that the Government of India is prepared to reconsider the policy that it has been pursuing till now I hope that such talks will be put an end to, that a firm declaration will be made on behalf of the Government that we stand on principle that we pursue a policy that will only pay us dividends and any deviation in the policy under pressure will lend us in greater trouble

Some hon. Members rose—

Mr. Chairman: There are some names before me. Shri Nayanar's name is given by the CPI (Marxist) party. Would he like to have his time just now, or next time?

Shri M. L. Sondhi: I would like to speak today

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara) I also want to speak. I have given notice.

Shri E. K. Nayanar (Palghat): After Mr Sondhi, I can speak.

Mr. Chairman: The resolution will continue.

Shri Surendranath Dwivedy: That does not matter; but I have given my name. *(Interruption)* What is the procedure?

Mr. Chairman: Mr. Sondhi.

Shri E. K. Nayanar: Sir, I rise to a point of order I represent one party. Before you give the chance to the other party, I may be permitted to speak now.

Mr. Chairman: I will give you time

Shri E. K. Nayanar: I am prepared to speak now

Mr Chairman: You will have your chance after Mr Sondhi. This resolution will be continued the next day

Shri E. K. Nayanar: I am opposing this resolution I will finish in five minutes Otherwise, it will take another 15 days for this to come up again.

Mr. Chairman: Please wait for some time You may start today, and continue the speech the next day Mr Sondhi

Shri E K. Nayanar: I appeal to you to give me time.

Shri M. L. Sondhi: Mr Chairman Sir, we are not here at all to advocate an escalation. We are here only to suggest the new tasks for diplomacy. These are tasks which any government must consider. because rethinking is an axiom in foreign affairs You have to continually rethink because the international environment is changing. I would, therefore, start with the question of the Dalai Lama. I submit that he is not only a religious authority comparable to any other religious authority in the world, but he represents in his person the full potentialities of an independent territorial authority in a very sizeable Asian country. I would, therefore,

submit that from the point of view of diplomacy, the world community is by and large sympathetic to the Tibetan cause. My own experience in Moscow suggests that large sections of Russian academic life take a very close interest in Tibet, are deeply upset by what is happening there and retain their feeling for an independent or autonomous entity called Tibet.

18 hrs.

At the 1394th plenary meeting of the UN General Assembly, the Indian delegate said:

> "Although the relationship between Tibet and India is centuries-old and has flourished in all its manifestations, whether religious, cultural or economic, we have always taken care not to make that relationship a political problem."

I think this statement is a contradiction, because it is not for you to make something political. What is politics is to be discerned as politics and to be accepted as such. Without any resort to any crusade against China, I entirely endorse that ultimately India and China have to be friends. These are great countries and they have to come together. But from the point of view of practical diplomacy, what prevents India from declaring that the Tibet question is a test case of the Chinese support for decolonisation? Let us ask them, in terms of the General Assembly resolution 1514 of the XV General Assembly, what their standpoint is. I think the Chinese will be even grateful to us for what we do. I say this in all seriousness.

I submit that the Chinese are at present in a xenophobia mood. But they do listen and communicate with the Russian, American and other Governments. India appears in their eyes—this is a point which some friends have urged here and I agree with them—as a 'yes' man for the different *status quo* world powers. Therefore, if Sino-Indian relations are seen by the Chinese as a real political relationship between them and India, they will tend to see us as a power in our own right instead of advocating this country or that country.

In spite of the physical occupation of Tibet by the Chinese, in spite of the fact that they have been speaking about the Dalai Lama and his Government in very derogatory terms, the fact remains that for a long time they respected the Dalai Lama. The Chinese are not unaware of the fact that the Dalai Lama continues to exercise enormous influence over the vast majority of the Tibetan people. Therefore, we should urge the political aspects of the Tibetan problem. In the beginning, it might have overtones of a fight, but it will be a peaceful fight; there will be no mounting of guns against each other; it will be a fight in the sense that we convince the Chinese—I might quote here some authorities. Latimer said that Tibet yields diminishing returns for any imperialism. The Chinese will find Tibet what Napolean found Spain was —something too difficult, something even counter-productive. To my mind, the Chinese have very little political advantage in holding to Tibet. But they have a military advantage. There are large caves in Tibet where missiles can be hidden. What the Americans and Russians do at great cost is available there under natural conditions.

Therefore, the problem for the Foreign Minister is that Tibet must become a denuclearised area,—something like the Rapacki plan. Rapacki plan was for disengagement between two sides in Europe. We need some such plan, call it Swaran Singh plan, if you like, for some disengagement in this area. We should take this away from nuclear confrontation. India will feel more secure if there are no Chinese missiles there. But that will require international inspection. Therefore, if the Dalai Lama Government is recognised as an Emigre

[Shri M. L. Sondhi]

Government, I do not see why my friends here should feel perturbed about it. We may go on talking like that. But the larger interests of our country demand that Tibet be made into a political issue, so that *vis-a-vis* China, there should be more talk ta'k, and less fight, fight.

Shri E. K. Nayanar: Sir, I rise to oppose this resolution. He who says that the Dalai Lama should be given political status and should be recognised as the head of the Emigre Government of Tibet, a government in exile, really wants to re-establish serfdom in Tibet. They explained about historical traditions thousand and two thousand years old. They want to re-establish the Dalai Lama's Government in Tibet. If we take thousand and two thousand years. . .

Mr. Chairman: The hon. Member may continue the next day. The *House stands adjourned till 11.00* on Monday.

18.06 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 3, 1967/*Asadha* 12, 1889 (*Saka*).

GMGIPND—LS II—1070 (Ai) LSD— 23-12-67—1000.